

नवा भारत



5

एयर डिफेंस को मिलेगी नई ताकत



6

वया बंगाल में बदलाव की आशा की जाए



7

बचत योजना पर मिलेगा तगड़ा ब्याज



8

चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ना जडेजा के लिए इमोशनल

उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे मप्र-उप्र

एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

दोनों राज्यों के बीच 2 महत्वपूर्ण एमओयू

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 31 मार्च. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि काशी विश्वनाथ धाम दुनिया के सात पवित्र स्थानों में शामिल है, वाराणसी की तरह उज्जैन भी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोनों ही शहरों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ी संभावनाओं को देखते हुए विकास कार्यों की शुरुआत की गई है.

दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक रिश्ते होने के साथ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं. उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश साझा विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं. इस क्रम में आज आयोजित एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन भविष्य को संभावनाओं को आधार प्रदान करेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को बनारस



HOTEL RAMADA, VARANASI
31 March 2026

में एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, पारम्परिक शिल्प, ओडीओपी और जीआई टैग उत्पादों, कृषि एवं खाद्य उत्पादों, निवेश अवसरों और पर्यटन संभावनाओं को एक साझा मंच देने के उद्देश्य से आयोजित सहयोग सम्मेलन का वाराणसी के होटल रामाडा में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव की

उपस्थिति में काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं श्री महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति तथा ओडीओपी की पहल को मजबूत करने, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा अंतर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच 2 महत्वपूर्ण एमओयू हुए. सम्मेलन में मुख्यमंत्री का उग्र की औद्योगिक संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा आत्मवी

स्वागत किया गया. सम्मेलन को उग्र के एमएसएमई मंत्री यूपी राकेश सचान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास तथा निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी संबोधित किया. वहीं प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में ओडीओपी नई पहचान के रूप में स्थापित हो रहा है. उज्जैन में 284 करोड़ रूपए की लागत से यूनैटी मॉल बनेगा, जो मध्य भारत में सबसे बड़ा

दोनों राज्यों के लिए केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अपनी नीति आधारित पारदर्शिता, उद्योगों के लिए उपलब्ध विशाल भूमि बैंक, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेशक हितैषी वातावरण के साथ नए अवसरों का केन्द्र बन रहा है. केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कार्यों की शुरुआत हुई है. इसका लाभ मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के जिलों को भी मिलेगा. यह परियोजना सिंचाई के साथ पेयजल सुविधा भी उपलब्ध कराएगी.

अस्पताल के लिए एक रुपये लीज पर 30 एकड़ जमीन दे रही सरकार

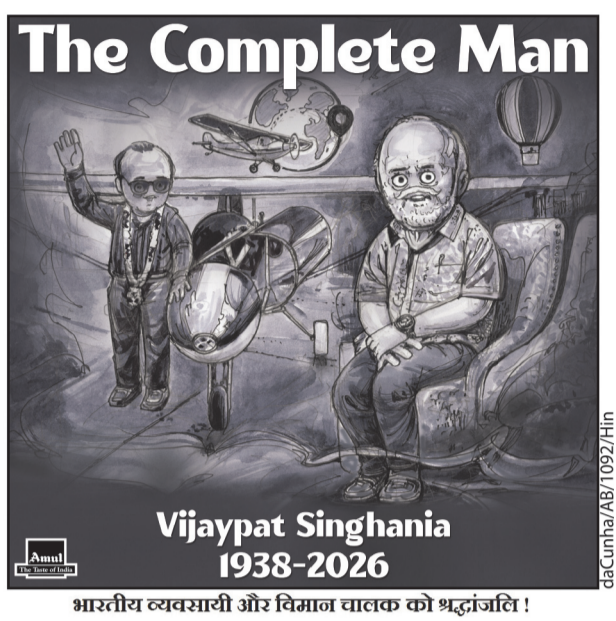
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार उद्योग और निवेश गतिविधियों को संचालित करने में मदद करने के लिए एक रुपये लीज पर 30 एकड़ जमीन दे रही है. मध्यप्रदेश वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाने के बाद वर्तमान वर्ष 2026 में कृषि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर हो गया है.

ओडीओपी शोकेस होगा. अन्य प्रदेशों के ओडीओपी उत्पाद भी यहां एक छत के नीचे होंगे. उत्तर

शिल्पकारों से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया संवाद

सम्मेलन स्थल पर दोनों राज्यों के शिल्पकारों के प्रमुख उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा शिल्पियों से संवाद किया. प्रदर्शनी में बांस शिल्प, मेटल क्रॉफ्ट, वस्त्र कला तथा जुट शिल्प के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं. यहां शिल्पकारों के परिश्रम को दर्शाया गया.

प्रदेश के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन से ओडीओपी प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी साझा की.



भारतीय व्यवसायी और विमान चालक को श्रद्धांजलि!

इमारत में आग से पांच की मौत

लिंगायत मीठी खाड़ी के पास सोसाइटी की इमारत में हादसा

एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से माहौल गमगीन

सूरत, 31 मार्च. गुजरात के सूरत में भीषण हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां लिंगायत मीठी खाड़ी के पास एक सोसाइटी की इमारत में अचानक आग लग गई. इस घटना में एक बच्चे समेत 5 लोग शूलस गए. इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया,

जहां पांचों की मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में कमरे से बड़ी मात्रा में साड़ियां बरामद हुईं. आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. आग लगते ही घर में अफरा-तफरी मच गई. चारों ओर धुआं उठता दिखाई दिया. घटना के बाद पूर्व महापौर दक्षिणभाई मावानी, डीसीपी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं. बता दें कि सभी मृतक एक ही परिवार के थे.

एक नजर में



भारतीय नौसेना को मिले तीन स्वदेशी युद्धपोत

नई दिल्ली. भारतीय नौसेना को तीन नए युद्धपोत प्राप्त हुए. इनमें एडवांस्ड गाइडेंड मिसाइल फ्रिगेट दुनागिरी, सर्वश्रेष्ठ पोत संशोधक और पनडुब्बी रोधी युद्धक उग्रते जलयान अग्रय शामिल हैं. इनका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया, जो स्वदेशी रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. एडवांस्ड गाइडेंड मिसाइल फ्रिगेट दुनागिरी सबसे परिष्कृत प्लेटफॉर्म में से एक है.

वीर विक्रम यादव बने डीजीसीए के महानिदेशक

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी वीर विक्रम सिंह यादव को मंगलवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) का नया महानिदेशक नियुक्त किया. ओडिशा कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी यादव इससे पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के तौर पर नियुक्त थे. वह मध्य प्रदेश कैडर के 1996 बैच के अधिकारी फैंज अहमद किदवई की जगह लेंगे, जिन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है.

सीबीआई ने दो एमसीडी अफसर किए गिरफ्तार

नई दिल्ली. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के उपायुक्त अभिषेक मिश्रा और लेखा अधिकारी दिव्याशु गौतम को रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया है. सीबीआई के अनुसार लेखा अधिकारी दिव्याशु गौतम ने एक लाइसेंस निरीक्षक से चार लाख रूपए की रिश्वत की मांग की थी. पीठिन ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. सीबीआई ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए योजनाबद्ध ढंग से जाल बिछाया और दोनों अधिकारियों को रोगे हाथों पकड़ लिया.

शीतलाष्टमी मंदिर में भगदड़ से आठ की मौत

घटना की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन

सीएम नीतीश कुमार ने किया शोक व्यक्त

राजगीर, 31 मार्च (वार्ता) बिहार में नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को शीतलाष्टमी मंदिर में भगदड़ से आठ लोगों की मौत हो गई तथा आठ श्रद्धालु घायल हो गए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मधुवा गांव स्थित शीतलाष्टमी मंदिर में सुबह श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए गए थे. अत्यधिक भीड़ से लोगों में भगदड़ मच गई. नालंदा के जिला पदाधिकारी



कुंदन कुमार ने बताया कि इस घटना में मृतक सात श्रद्धालुओं की पहचान कर ली गई है. उन्होंने कहा कि मृतक के आश्रितों को छह लाख रुपये का तत्काल मुआवजा दिया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने बताया कि इस घटना के बाद एसआईटी टीम का

प्रभावित देशों को अमेरिका से तेल लेना चाहिए : ट्रम्प

यूएस-इजराइल और ईरान के बीच जंग का 32वां दिन

वॉशिंगटन, 31 मार्च. यूएस-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का 32 दिन पूरे हो चुके हैं. जंग के कारण कई देश कूड ऑयल के लिए परेशान हैं. इन हालातों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि अब अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा. प्रभावित देशों को खुद ही अपने हालात संभालने होंगे.

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जो होर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे



हैं, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कोई कमी नहीं है. ट्रम्प ने कहा कि अगर देश चाहें, तो हिम्मत दिखाएं और खुद होर्मुज स्ट्रेट जाकर तेल लें. अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे वे अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए. अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि ईरान काफी हद तक कमजोर हो चुका है और सबसे मुश्किल काम पहले ही पूरा हो गया है.

अमेरिका ने दागे 2000 पाउंड के 'बंकर-बस्टर' बम

अमेरिका-इजरायल और ईरान की बीच संघर्ष दिन-दिन भीषण होता जा रहा है. अब जानकारी आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के प्रमुख शहर इस्फाहान में एक बड़े हथियार गोदाम पर हमला किया है. इस हमले में 2000-पाउंड (लगभग 907 किलोग्राम) के भारी बंकर-बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है. इस हमले का उद्देश्य ईरान की रक्षा क्षमताओं को कमजोर करना बताया जा रहा है. साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस हमले से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. हमले के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमाकों का एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान की ओर उठती आग की लपटें और धुंध का विशाल गुबार साफ देखा जा सकता है.

1950 करोड़ की लागत से खरीदे जाएंगे माउंटेन रडार

हवाई निगरानी को मजबूत बनाने की पहल

नई दिल्ली, 31 मार्च. रक्षा मंत्रालय ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई निगरानी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय वायु सेना के लिए संबंधित उपकरणों और आवश्यक बुनियादी ढांचे सहित दो माउंटेन रडार की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत से प्रमुख पूंजीगत अधिग्रहण अनुबंध किया है.

इस अनुबंध पर श्रेणी के अंतर्गत मंगलवार को यहां रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए. इसे आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया के तहत भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह पर्वतीय रडार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास स्थापना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है.

जवानों को समय पर नहीं दिया वेतन

सीएजी रिपोर्ट संसद में पेश

मिलिट्री अस्पतालों में मिली कई कमियां

नई दिल्ली, 31 मार्च. सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश की गई. रिपोर्ट में बताया गया है कि कई सेना के जवानों को उनके वेतन और भत्तों का समय पर भुगतान नहीं किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, प्रोविजनल फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की समीक्षा समय पर नहीं होने के कारण कई कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय बड़ी राशि

दवाओं की कमी और फंड का दुरुपयोग

आर्मड फोर्स मेडिकल स्टोर्स डिपो द्वारा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति में कमी भी पाई गई. कॉमन ड्रग लिस्ट की दवाएं भी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थीं. दो डिपो में दवाओं का समय पर नवीनीकरण नहीं हुआ, जिससे लगभग 13.52 करोड़ की दवाएं फंस गईं. की निगरानी के लिए ऑटोमैटेड सिस्टम लागू किया जाए. रिपोर्ट में मिलिट्री अस्पतालों की समस्याओं का भी जिक्र किया गया है. अस्पतालों की अधिकांश इमारतें पुरानी हैं और उनकी उचित जांच नहीं हुई है. एक मामले में, लैंसडाउन के मिलिट्री अस्पताल का एक हिस्सा जून 2022 में गिर गया था. साथ ही हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग की कमी भी देखी गई.

मानव तस्करी के मामलों में लापरवाही पर फटकार

नई दिल्ली, 31 मार्च. सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी और लापता व्यक्तियों से संबंधित मामलों में कई राज्यों और अधिकारियों को जवाब नहीं देने के लिए फटकार लगाई है और सर्वोच्च अदालत के एक राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के निर्माण का निर्देश का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है.

पीठ ने अपने आदेश में रिकॉर्ड किया कि नोटिस जारी करने के बावजूद भारत सरकार और हरियाणा, मिजोरम, केरलम, ओडिशा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ. इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.



सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दी अवमानना की चेतावनी

पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को 16 अप्रैल तक व्यक्तिगत रूप से पुष्टि किए गए हलफनामे दाखिल करने होंगे. इसमें उनकी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण दिया जाएगा. अन्यथा उन्हें इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा. पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुपालन नहीं करने पर कड़े परिणामों का सामना करना पड़ेगा और चेतावनी दी कि परिणामस्वरूप अवमानना नोटिस जारी किए जा सकते हैं.

सौगात पीएम ने वाव-थराड में 20 हजार करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास, विपक्ष पर साधा निशाना

कांग्रेस हालात बिगाड़ने की कर रही कोशिश : पीएम

अहमदाबाद, 31 मार्च. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के दौरे पर थे. उन्होंने वाव-थराड में 20 हजार करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जंग की वजह एनर्जी संकट बढ़ रहा है. ऐसे संकट में भी भारत ने हालात को नियंत्रण में बनाए रखा है. मोदी ने कहा कि मुश्किल समय में भी कांग्रेस जनता को भड़काने और अफवाह फैलाने में लगी है. उनका आरोप है कि कांग्रेस सियासी लाभ के लिए हालात बिगाड़ने और पेट्रोल पंपों पर भीड़ जुटाकर अव्यवस्था फैलाने की



कोशिश कर रही है. इससे पहले उन्होंने साणंद में केयस सेमीकॉन के आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट का और गांधीनगर में सम्राट सम्प्रति

891 करोड़ की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का लोकार्पण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान राज्य में रेल अवसरचना को सुदृढ़ करने के लिए 891 करोड़ के महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं राष्ट्र को समर्पण किया. इन परियोजनाओं में खेडब्रह्मा-हिम्मतनगर-रेल लाइन का लोकार्पण तथा खेडब्रह्मा-हिम्मतनगर-अहमदाबाद (असाववा) नई रेल सेवा का शुभारंभ, गांधीधाम-आदीपुर रेल लाइन के मल्टी-ट्रैकिंग एवंकालानुस-जामनगर रेल लाइन के दोहरीकरणका राष्ट्र को समर्पण शामिल है. ये सभी परियोजनाएं गुजरात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों-उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ को सशक्त कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए राज्य के समग्र विकास को नई गति दे रही हैं.

सुको से राजस्व न्याय सेवा बनाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके कहा गया है कि अयोग्य कानूनी पेशेवर जमीन विवादों पर फैसले दे रहे हैं. लिहाजा इसके लिए राजस्व न्याय सेवा की स्थापना की जाए. साथ ही ऐसे मामलों पर फैसला सुनाने वाले राजस्व अधिकारियों के लिए न्यूनतम कानूनी योग्यता और हाई कोर्ट के परामर्श से ट्रेनिंग मॉड्यूल निर्धारित किया जाए. वकील अधिनियम उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि लगभग 66 प्रतिशत दीवानी मामले जमीन विवादों से जुड़े होते हैं और इसमें मुख्य खामी यह है कि इन पर ऐसे अधिकारी फैसला दे रहे हैं, जिनके पास औपचारिक कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं है. इसकी वजह से गलत और असंगत फैसले आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई दो अप्रैल को कर सकता है. वकील दुबे द्वारा तैयार याचिका में कहा गया है कि इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विचार किया था, लेकिन उसके निर्देशों को आज तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है.